

Employee Provident Scheme

A 3-192

Schedule 1 - Manufacturing Industry की List.

Schedule 2 - scheme को बनाने वाले provisions **EPF**

Schedule 3 - Pension scheme के provisions **EPS**

Schedule 4 - Employee's deposit linked insurance scheme  
कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना **EDLIS**

**Sec-5**

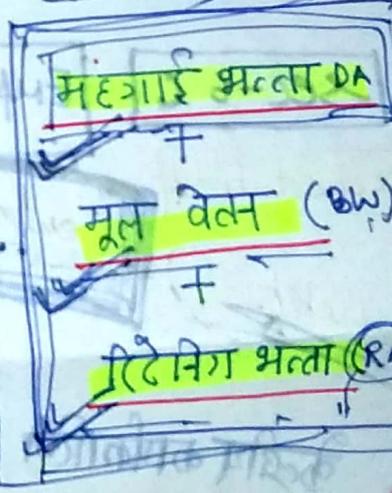
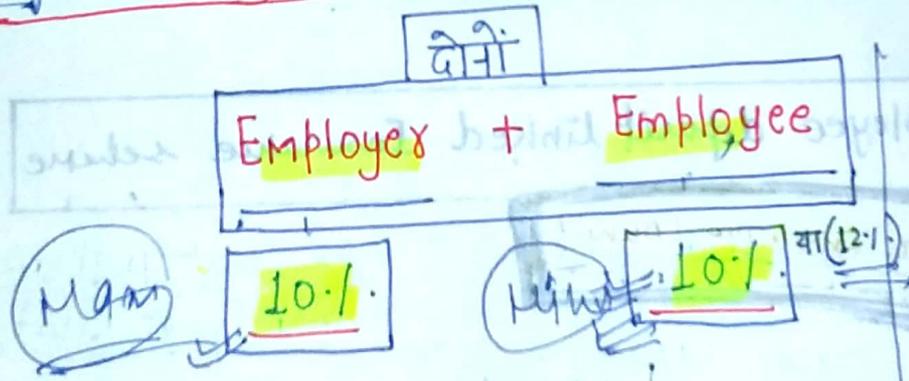
Employee provided fund scheme.

कर्मचारी के बचत के लिए → Purpose

**Schedule-2**

Central gov. → official Gazette से Notification → EPF schemes कहेलायेगी

**Schemes**



Note - Employee (10%) को बढ़ा सकेगा लेकिन Employer उससे ज्यादा के लिए bounded नहीं होगा।

**Central Board of Trustees** → देखभाल करेंगे

current में 43 सदस्य

कर्मचारी

2(f) Employee

2e Employee

Any person wages के लिए किसी कार्य के **directly** **Indirectly** Employer से मजदूरी प्राप्त को।

- Employee है
- मजदूरी के लिए **2(d) Factory** में काम को
- काम के लिए **Physically** **other**
- नियोजक **direct** → सीधे काम (मालिक) **Indirect** → Indirect → (A) → (B) → (C)

(But part time न है → permanent है)

\* **Trainee** → अगर केवल Training के बाद पला जाये → Exclude  
\* Training के बाद promotion ले जाओ → **Include**

\* **Apprentice Act-1961** → अगर Registered है तो **Exclude**  
without Registration → **Include**

Sweeper / चपरासी / लिपिक → **Include**  
\* ठेके पर काम करने वाला → **Include**  
\* घाट ले जाकर काम करने वाला → **Include**

1) **आंध्र University v/s RPF** University में लगा Press, Factory है अतः **Include**

2) **लाली सेन v/s RPF** **car की servicing + Repairing** → **Factory** → **Include**

**Sec-10**

**Protection Against Attachment**

सेवा के साथ  
सेवा के बाद भी

मोतीलाल शर्मा v/s कुटी मियां  
रामेश्वर (लाल अग्रवाल)

कुर्क किये जाने के विरुद्ध संरक्षण

Protection

assigned / समनुदेशित

charged / भारित

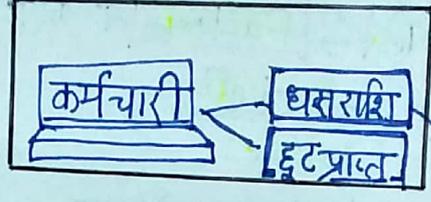
प्रेसिडेंसी काउन्स इन्साल्वेन्सी Act 1901

प्रान्तीय दिवालिया Act 1920 से protection

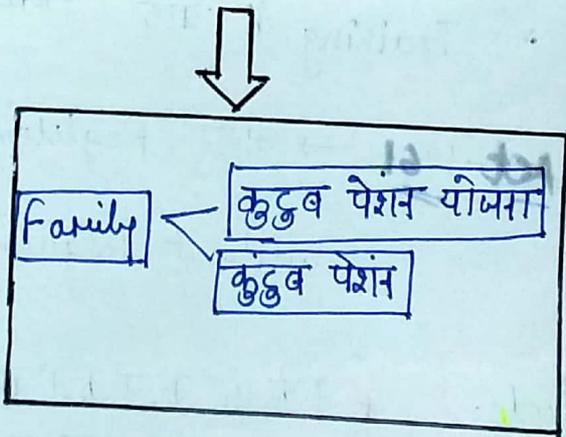
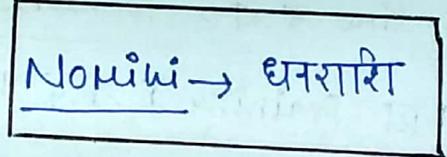
Protection

**10(1)**

ऋण या दायित्व  
deeree आदेश



without any change/assigned.



**10(2)**

”

more care laws

**10(3)**

”

10

किसी भी condition में नहीं इसे को assigned नहीं charged

किसी भी Court के decree order से कुर्क नहीं की जा सकेगी

Leading case

मोतीलाल शर्मा v/s University of Rajasthan

स्टेनोग्राफर का कमेरे का बकाया किराया तो PF लेका.

Judgement -> Contract अलग PF अलग

# EC-13 INSPECTOR

किसी भी (3) scheme के लिए

Inspector का Appointment

Appropriate Government 2(a) के द्वारा

Official Gazette की Notification

से की जा सकेगी।

13(1) → Appropriate Government को power कि Notification से 1 या 1+ को Appoint को

## Powers

① Act/scheme/Insurance scheme के सम्बन्ध में दी गई किसी Information की सत्यता की जांचना

② Act/scheme/I. scheme के किसी provision का पालन इस Establishment में किया जा रहा है/नहीं

↓  
③ लागू होने के बाद check

④ sec-17 में दी गई छूट employee के द्वारा घूरी की गई है या नहीं।

↳ (छूट देने की powers)  
A-4 को

## Powers को use करते हुये duties

① employer/ ठेकेदार जिससे sec-8(A) में वसूली है से स्वयं लेने की duty. ★

② स्वयं सहायक → प्रवेश + तलाशी + details की जांच

③ → ② का परीक्षण

④ photocopy + Gine के condition में seize कर सकता है

⑤ Act के other works



Liability

- (1) वैयक्तिक क्षति हुई हो
- (2) क्षति दुर्घटना के कारण हुई हो
- (3) दुर्घटना नियोजन से उद्भूत एवं नियोजन के अनुक्रम में हुई हो
- (4) मृत्यु या निराश्रयता हुई हो

- (1) नियोजन से उद्भूत
- (2) नियोजन के अनुक्रम में
- (3) doctrine of Direct Nexus
- (4) doctrine of Added peril

Exceptions:- कब Liability नहीं होगी

- (1) Injury से हुई disablement उदियों से ज्यादा न रही हो
- (2) ऐसी Injury जिसमें मृत्यु या पूर्ण निराश्रयता नहीं हुई है, नियोजक निम्न पाँचास (defence) प्रस्तुत कर सकता है-

- (1) कर्मचारी पर दुर्घटना के समय, मरिटा या औषाधि का प्रभाव था।
- (2) कर्मचारी की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से बनाये गये किसी नियम या निर्देश की कर्मचारी द्वारा जानबूझकर अवज्ञा की गई थी।
- (3) कोई ऐसा रसोपाय या अन्य युक्ति जिसके बारे में कर्मचारी जानता था कि वह कर्मचारी का श्रेय सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त की गई है, वह कर्मचारी द्वारा जानबूझकर हटाया गया था या उसकी अवहेलना की गई थी।

उपजीविकाजन्य रोगों के सम्बन्ध में नियोजकका दायित्व - schedule-3 उपजीविका जन्य रोग।

added peril -> Not apply  
RB मून्दा & कम्पनी v/s मुसम्मत भनवारी  
(पेट्रोल टैंक + मापित की तीली + compensation.)

- schedule 3
- (i) विशेष अवधि नहीं।
  - (ii) कम से कम 6 माह की लगातार सेवा
  - (iii) केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

अपराध मॉटर सर्विस् v/s पियमल

काम से लौटने के 2 घण्टे बाद चोकीदार की मृत्यु -> Liable

पेयर्सन मद्रास चोर्ट v/s कमला

भोजन या जलपान हेतु जाते हुये घटित दुर्घटना नियोजन के अनुक्रम में कही जायेगी व कर्मकार प्रतिकार करने का हकदार होगा।

Burden of Proof: claimant पर-

वार्डशाकरी v/s न्यूमारेचौक मि० लिमिटेड

जस्टिस JHEJAL -> "यदि compensation के लिए Burden of proof claimant पर हो तो यह अन्वय के समान है"

सेन्ट हेलेन्स कोलियरी कम्पनी लि०  
v/s  
ह्यूल्सटन

**सामाजिक सुरक्षा**

**परिचय:-** किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का यदि हम सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएँ दी जानी अति आवश्यक होती हैं जिससे उनके स्वयं के साथ ही साथ परिवार की सुरक्षा की भावना को बल मिलता है। इन्हीं सुविधाओं व जोखिम से बचाव के लिए किये गये प्रयासों के समूह की संयुक्त अवधारणा को 'सामाजिक सुरक्षा' कहा जाता है।

**सामाजिक सुरक्षा का आशय व प्रकृति:-** 'सामाजिक सुरक्षा' शब्द की उत्पत्ति 1881 में जर्मनी में मानी जाती है औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1935 में विलियम वैबरिन के द्वारा की गई जिन्के अनुसार 'सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट या कम कमाई के समय होने वाले आतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करता है'। सामाजिक सुरक्षा की प्रकृति प्रगतिशील विचारधारा को धारण करती है।

**विभिन्न संविधियों में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान:-**

**अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में-**

ILO अनुच्छेद-22+25 सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य देखभाल व आय की सुरक्षा शामिल है।

UDHR 1948 सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में रीजगाट, भोजन, निवास स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। (- Art-25 Standard of living)

UN सामाजिक सुरक्षा अभिसमय 1952 - वृद्धावस्था पेंशन, व्याधियों का जीवन यापन, बेरोजगारी, अक्षमता से सुरक्षा ही सामाजिक सुरक्षा है।

- (9) ICCPR
  - (10) ICESCR
  - (11) CEDAW
- Also Related to Social security

Nature -

main conventions  
1952  
1962  
1964

**भारतीय संविधान के परिप्रेष्य में:-**

भारत के संविधान का आधारभूत ही सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करने का निर्देश दिये गये हैं कि वे विधायन में उसका अवधि समावेश करें। यह कदम की आवश्यकता नहीं कि एक सामाजिक सुरक्षा योजना की सम्भाव्यता बुनियादी तौर पर सुलभ साधनों की सीमा पर निर्भर करती है यही मुख्य कारण है कि भारतीय संविधान में यह विषय मूल-अधिकारों के भाग-3 में अपना स्थान सुनिश्चित करने में असफल रहा। (अनु०-23, 24 में प्रावधान)

- अनु० 41- कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा लौक सहायता पाने का अधिकार
  - अनु० 46- समाज के दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा व अर्थ सम्बन्धी हितों में वृद्धि
- उसके अतिरिक्त अनु०- 15(3), 39, 42, 43(क) में भी प्रावधान किये गये हैं।

Preamble  
Fundamental right  
DPSP [7th sc. 23+24]

**सामाजिक सुरक्षा के आधारभूत तत्व:-**

सामाजिक सुरक्षा का निर्माण विभिन्न दशाओं में नागरिकों

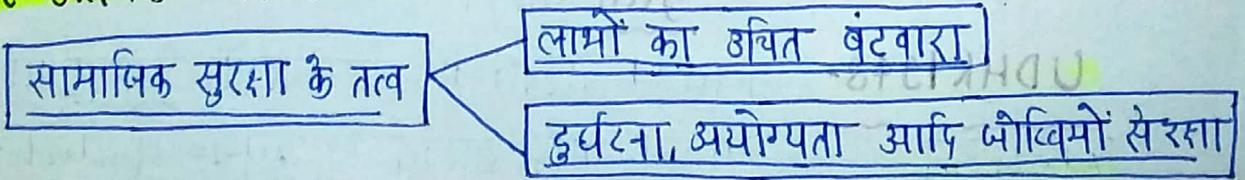
की सहायता करने वाले तत्वों से मिलकर होता है-

- \* अयोग्यता - इसमें नागरिकों को पेंशन सुविधा दी जाती है।
- \* शिथिलता - आश्रितों के भरण-पोषण हेतु मुआवजा दिया जाता है।
- \* रोजगार की सुरक्षा - विधायन के माध्यम से रोजगार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है।

**सामाजिक न्याय:- सामाजिक सुरक्षा का एक सारगर्भित आयाम-**

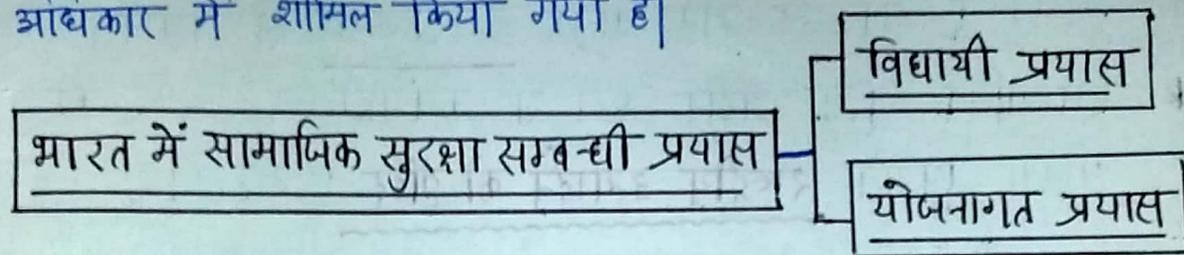
किसी भी

राष्ट्र के लिए "राष्ट्र की प्रचलित बुराइयों को दूर करते हुये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति ही सामाजिक सुरक्षा कहलाती है"



यह कहा जाता है कि "सामाजिक न्याय की तुला किसी भी ओट झुकी नहीं होती है" तथा यह Haves व Haves Not के मन्तव को खत्म करती है। भारतीय संविधान के अनु०-39 में कहा

दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधायकों में सामाजिक  
 सहाय सम्बन्धी कतिपय सिद्धान्तों को लागू करे उच्चतम साधन्य द्वारा  
 विभिन्न विधियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा व सहाय को बढ़ावा दिया  
 जाना भी उल्लेखनीय काम है। और काम के अधिकार\* को जीवन के  
 अधिकार में शामिल किया गया है।



**विधायी प्रयास:-** भारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रथम प्रयास  
 1944 में PD आडेरकर के नेतृत्व में किया गया  
 तथा प्रथम सामाजिक सुरक्षा कमीशन गठित किया गया। इसके अलावा  
 कानूनों के माध्यम से भी यह सुनिश्चित किया जाने का प्रयास होता  
 रहा है जिसे निम्नलिखित है-

- \* कर्मचारी प्रतिकर अधि० 1923 - कर्मचारी व आगितों को प्रतिकर
- \* कर्मचारी राज्य बीमा अधि० 1948 - बीमा की सुविधा
- \* मातृत्व लाभ अधि० 1961 - 26 सप्ताह का अवकाश (18+8)
- \* भारतीय संविधान में किये गये प्रावधान - मूल अधिकार में व DPSP में।

**योजनागत प्रयास :-** विधायी प्रयासों के अतिरिक्त सरकार योजनाओं  
 के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान  
 करती है-

**योजना**

- प्राधान्यमंती जन धन योजना
- अटल पेंशन योजना
- जीवन ज्योति बीमा योजना-
- मुड़ा योजना

**सुरक्षा का मूल तत्व**

- आर्थिक सुरक्षा
- पेंशन या वृद्धावस्था की सुरक्षा
- बीमा सहायता
- उद्योगों में मदद

**सामाजिक सुरक्षा से होने वाले लाभ:-**

- \* कर्मचारी को दुर्घटना के समय अतिरिक्त व्यय व आय साधन न होने से होने वाली दोहरी मात्र से बचाव।
- \* सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से कर्मचारी में सन्तुष्टि की भावना जिससे राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सहायता।
- \* मानवीय मूल्यों की स्थापना व मूल अधिकारों की वृद्धि में भी सहायक।

सामाजिक सुरक्षा विकास का पैमाना है।

**सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रांसगिक वादा**

**वाद**

**अभिनिर्धारित अधिकार**

PUDR v/s भारत संघ

MC मेहता v/s भारत संघ

बन्धुआ मुक्ति मोर्चा v/s भारत संघ

भोपाल गैस त्रासदी केस

2018

पर्यावरण का अधिकार

**निष्कर्ष:-**

सामाजिक सुरक्षा के उपायों की पृष्ठभूमि में निहित धारणा यह है कि एक ऐसा नागरिक जिसने देश के कल्याण में योगदान दिया है या योगदान की आशा की है उसे अवश्य ही कतिपय कठिनाइयों व विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुये भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री बी. वी. गिरि ने कहा था कि “सामाजिक सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को उस जोखिम में सहायता प्रदान करना है जिसमें वह स्वयं तथा उसका परिवार मिलकर भी उसे अपनी रक्षा करने में असमर्थ हों”।

# Social Security Articles

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ व्यक्ति को उस जोखिम में सहायता प्रदान करना है जिसमें वह तथा उसका परिवार मिलकर भी उससे अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो।"

में जर्मनी से - King William - मजदूरों को बीमा की सहायता।

- पूर्व राष्ट्रपति की.वी. गिरि

UK - **विलियम वैबरिन** Social Insurance Allied Services.

सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय जब उसकी कमाई कम हो जाये या मृत्यु, विवाह आदि में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करती है।"

**ILO** यह सुरक्षा जो समाज, **अपित संगठनों** के माध्यम से **अपने सदस्यों** के साथ धरित होने वाली कुछ बचतों और **जोखिमों** से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है जोखिम - दुर्घटना, रोग, मातृत्व अयोग्यता, वृद्धावस्था, बेरोजगारी आदि।

**Provisions:** **ILO** - Article - **22+25**

1952 + 1962 + 1964 - ILO ने SS सम्मेलन भी कराया है।

**UDHR 1948**

**Art-22**

समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय & अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न में आवश्यक आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक है।

**Article-25**

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे एवं उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो, इसके अन्तर्गत खाना, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, सम्बन्धी सुविधाएँ और आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं। बुढ़ापा आदि किसी अन्य ऐसी ही परिस्थिति में आजीविका का साधन न होने पर, जो उसके कारण से बाध हो सुरक्षा का अधिकार।

**ICCPR 1966**

**Article-9**

"वर्तमान प्रतिज्ञापन के पक्ष देश सामाजिक सुरक्षा सहित सामाजिक बीमा के सभी अधिकारों को मान्यता देते हैं" (Article-10 also provides)

**UN सामाजिक सुरक्षा अभिसमय 1952:**

वृद्धावस्था पेंशन, **आश्रितों का जीवन बीमा**, **बेरोजगारी**, अक्षमता आदि की सुरक्षा → सामाजिक सुरक्षा है।

**Indian Constitution:**

सामाजिक न्याय → लक्ष्य + प्रयत्नित बुराईयों को इत काना।

"की तुला किसी ओर सुकी नहीं है।"

**Part-3 - 14, 15, 16, 21 में**

**Part 4 - 39, 41, 42, 43, 43 (क) - 42+76**

**7th Schedule**

**प्रविष्टि 23 & 24**

Social Security & समाज कल्याण के सम्बन्ध में विधि बनाने का अधिकार राज्य एवं संघ दोनों को है।

**1949 PD आर्डर** - प्रथम सामाजिक सुरक्षा कमेटी

Social security के steps

**विधायी प्रयास**

**योजनात्मक प्रयास**

- कर्मचारी प्रतिक आधि. 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधि. 1948
- मातृत्व लाभ अधि. 1941
- EPF 1952

मरीणा - काम का अधिकार, PJDY - आर्थिक सुरक्षा

APY - वृद्धावस्था पेंशन, ABY - जन-आरोग्य लाभ

JJB - Life Insurance की व्यवस्था

इन्द्रधनुष - महिला जीवन कौशल प्रशिक्षण मविध्यानिधि अधि. 1952

900

LBM-672

**LL.B. (Hons.) Third Semester  
Examination, 2019-20**

**LABOUR LAW**

**(Social Security Legislation)**

**Paper : III**

**(Code : 525)**

**Time : Three hours**

**Max. Marks : 60**

45

**Note :** All questions are compulsory. Q. No. 2-5 have internal options, word limit for Question No. 1 is 1200 words and for question No. 2-5 600 words each. Extra writing shall be penalised. Marks carried by each question are indicated against is question concerned.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 2-5 में आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न 1 की शब्द सीमा 1200 शब्दों की है तथा प्रश्न 2-5 के उत्तर की शब्द सीमा 600 शब्द है। अतिरिक्त लेखन दंडित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं।

1. Write short notes on following :

निम्न पर टिप्पणी लिखिए :

(a) Notional extension of employer premises.

नियोजक के परिसर का भावात्मक विस्तार

LBM-672

(1)

3  
=

(b) Permanent Disability.

पूर्ण स्थायी निःशक्तता 3

(c) Factory.

कारखाना 4

(d) Inspector under EPF & M. P. Act, 1952.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत निरीक्षक 4

2. Discuss the conditions of labour from the ancient society to the age of industrialisation.

प्राचीन काल से लेकर औद्योगिक युग तक श्रमिकों की स्थिति की विवेचना कीजिए।

OR

अथवा

Discuss the origin of labour laws beginning with the era of industrialization.

श्रमिक कानूनों का उद्भव औद्योगिक युग में हुआ विवेचना कीजिए। 7

3. Explain the meaning & scope of the expression social security discuss the development of law relating thereto in India.

पद सामाजिक सुरक्षा के अर्थ एवं विस्तार को समझाइये तथा भारत में इससे सम्बन्धित कानून के विकास की विवेचना कीजिए। 8

OR/अथवा

(2)

LBM-672

'ILO has played an important role in promoting the enactment of labour laws in India.' Discuss.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का भारत में श्रमिक कानूनों के अधिनियमन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। विवेचना कीजिए।

4. Explain the meaning and extent of expression "accident arising out of and in the course of employment" with the help of decided cases.

निर्णीत वादों की सहायता से पद नियोजन से उद्भूत एवं नियोजन के अनुक्रम में घटित दुर्घटना के अर्थ एवं विस्तार को समझाइये।

OR

अथवा

Discuss facts and circumstances under which employer has been, exempted from the liability to pay compensation to the employees under Employees compensation Act, 1923.

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। जिनमें नियोजक को कर्मचारियों को प्रतिकर देने के दायित्व से मुक्त किया गया है। 7

5. Discuss the category of establishment to which employees PF and MP Act, 1952 applies. Can an establishment be exempted from application of the provision of Act?

उन संस्थानों की विवेचना कीजिए जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 लागू होता है। क्या इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू किये जाने से किसी संस्थान को छूट दी जा सकती है?

LBM-672

(3)

OR

अथवा

Explain the various schemes under employees PF & MP Act, 1952. To what extent this Act has provided social security ?

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को समझाइए। कहाँ तक इस अधिनियम के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। विवेचना कीजिए।

---

9